भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 297

सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024 / 25 अग्रहायण, 1946 (शक)

ईपीएफओ के नए अंशदाताओं की संख्या में गिरावट

***297. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, एक साल पहले की तुलना में वर्ष 2023-24 में ईपीएफओ में कुल नए अंशदाताओं को जोड़े जाने में 4 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है और इनकी संख्या 1.09 करोड़ हो गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी गिरावट के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा ईपीएफओ की सदस्यता पर आर्थिक मंदी और नौकरी छूटने के प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

*****

“ईपीएफओ के नए अंशदाताओं की संख्या में गिरावट” के संबंध में श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील द्वारा दिनांक 16.12.2024 को पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 297 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): ईपीएफओ वर्ष 2018 से मासिक पेरोल डेटा जारी कर रहा है। यह डेटा प्रत्येक महीने की 20 तारीख को जारी किया जाता है और ईपीएफओ के वेब पोर्टल http://www.epfindia.gov.in>> Payroll Data पर पब्लिक डोमेन के लिए उपलब्ध होता है।

वर्ष 2020-21 से जोड़े गए नए ईपीएफ अभिदाताओं की संख्या निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**नए ईपीएफ अभिदाताओं की संख्या**
2020-21	85,48,898
2021-22	1,08,65,063
2022-23	1,14,98,453
2023-24	1,09,93,119
2024-25 (अप्रैल-सितंबर 24)	61,46,445

उपरोक्त तालिका स्पष्ट दर्शाती है कि ईपीएफओ में साल दर साल सतत रूप से एक करोड़ से अधिक नए अभिदाता जुड़े हैं। जबकि एक ओर, वर्ष 2022-23 में ईपीएफ अभिदाताओं की अधिक संख्या की वजह कोविड-19 के कारण वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान ईपीएफओ में पंजीकरण के बैकलॉग को कहा जा सकता है, वहीं दूसरी ओर, यह कोविड के बाद की अवधि में आर्थिक गतिविधियों में सुधार को दर्शाता है।

चालू वित्तीय वर्ष में, गत वित्तीय वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2023-24 के 56% नए ईपीएफ अभिदाता पहले छह महीनों में ही जुड़ चुके हैं, जिससे यह नए ईपीएफ अभिदाताओं में बहुत अधिक वृद्धि दर्शाती है।

(ग) और (घ): अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए, सरकार ने ईपीएफओ में नामांकन के आधार पर केंद्रीय बजट 2024-25 में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है।

*****